नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 079
दि. 21.12.2025,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

मुंबई में बीएमसी चुनाव: उद्धव ठाकरे की सियासी बिसात पर होगी आख़िरी परीक्षा

मुंबई। 16 जनवरी 2026 महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक निर्णायक मोड़ के रूप में उभर रहा है, क्योंकि इसी दिन बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) सहित राज्य की 29 नगरपालिकाओं के चुनाव परिणाम घोषित होंगे। ये नतीजे केवल स्थानीय निकायों की सत्ता तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि महाराष्ट्र के प्रमुख राजनीतिक दलों की दिशा तय करेंगे और उनके भविष्य की तस्वीर को भी आकार देंगे। इस मैदान में सबसे बड़ी चुनौती शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे के सामने है, जिनके लिए बीएमसी चुनाव सिर्फ एक स्थानीय निकाय की लड़ाई नहीं बल्कि उनके राजनीतिक अस्तित्व, पारिवारिक विरासत और भविष्य की परीक्षा बन चुका है।

उद्धव ठाकरे के राजनीतिक जीवन में बीएमसी का महत्व इस बात से स्पष्ट होता है कि 1996 से लगातार शिवसेना मुंबई की सत्ता में काबिज रही है और शहर की राजनीति में उनकी पकड़ मजबूत रही। 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना दो गुटों में बंट गई, और 2024 के विधानसभा चुनाव में उद्धव की पार्टी को केवल 20 सीटें और 10 प्रतिशत के करीब वोट शेयर मिला। इस हार ने उनकी राजनीतिक साख को चुनौती दी और बीएमसी अब उनके लिए अंतिम मजबूत दुर्ग बन गया है।

बीएमसी में कुल 227 पार्षद सीटें हैं, और मेयर बनने के लिए 114 सीटें जरूरी हैं। इस बार उद्धव ठाकरे को न केवल बीजेपी-शिंदे गठबंधन का सामना करना है, बल्कि कांग्रेस और

अन्य क्षेत्रीय दलों से भी चुनौती मिलेगी। चुनावी गणित को और जटिल बनाते हुए मुंबई में मुस्लिम वोट बैंक लगभग 20–22 प्रतिशत आबादी के साथ है, और सपा तथा एआईएमआईएम की सक्रियता के कारण यह वोट अब यूबीटी के लिए बंट सकता है। इससे शहर की लगभग 40–45 सीटें उद्धव के लिए निर्णायक मोड़ बन सकती हैं।

उद्धव ठाकरे ने बीएमसी पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पुराने मतभेद भुलाकर मनसे प्रमुख राज ठाकरे से गठबंधन किया। यह गठबंधन ठाकरे परिवार की राजनीतिक विरासत और पार्टी की पहचान को बचाने की रणनीति का अहम हिस्सा है। वहीं कांग्रेस का अलग रुख और भाजपा-शिंदे गठबंधन की ताकत उनकी राह में चुनौती बन रही है। भाजपा का स्पष्ट लक्ष्य है कि बीएमसी पर कब्जा कर वह न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक रूप से भी मुंबई में अपना दबदबा कायम करे। इस बार बीजेपी ने 150 सीटों के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को अपना लिया है, जिससे उद्धव ठाकरे के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है।

बीएमसी का बजट लगभग 74,427 करोड़ रुपये का है, जो शहर की राजनीति और पार्टी संगठन के लिए आर्थिक सहारा भी प्रदान करता है। इस बजट का नियंत्रण पार्टी को चुनावी रणनीति और शाखाओं को मजबूत करने का अवसर देता है। उद्धव ठाकरे के लिए यह चुनाव केवल सत्ता का सवाल नहीं है, बल्कि बाल ठाकरे की विरासत, शिवसेना (यूबीटी) की पहचान और मुंबई की मराठी मानुष की राजनीति को बचाने की लड़ाई है। अगर बीएमसी पर उनका नियंत्रण मजबूत रहता है, तो यह आगामी विधानसभा चुनावों में उनकी राजनीतिक वापसी का संकेत बनेगा, वहीं हार की स्थिति में उनकी सियासी पकड़ कमजोर हो सकती है।

इस प्रकार, मुंबई का बीएमसी चुनाव अब सिर्फ स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं रह गया है। यह महाराष्ट्र की राजनीति, उद्धव ठाकरे के सियासी भविष्य, शिवसेना (यूबीटी) की पहचान और देश की आर्थिक राजधानी में सत्ता संतुलन की निर्णायक परीक्षा बन गया है। इस चुनाव के परिणाम न केवल उद्धव ठाकरे की राजनीतिक बिसात तय करेंगे, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरणों और गठबंधनों की दिशा भी निर्धारित करेंगे।

जम्मू-कश्मीर के रतले हाइड्रो प्रोजेक्ट में सुरक्षा खतरा, 29 मजदूरों के टेरर लिंक उजागर

किश्तवाड़। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर बन रहे रतले हाइड्रो प्रोजेक्ट की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई जा रही है। जम्मू-कश्मीर पुलिस के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे 29 मजदूरों के टेरर लिंक पाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि ये कर्मचारी देश विरोधी गतिविधियों और क्रिमिनल मामलों में शामिल रहे हैं या उनके परिवार में ऐसे लोग हैं। इस संबंध में कंपनी को निर्देश दिया गया है कि इन कर्मचारियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाए और भर्ती पर फिर से विचार किया जाए, क्योंकि ऐसे लोग परियोजना की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं।

850 मेगावॉट क्षमता वाला रतले हाइड्रो प्रोजेक्ट नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHPCL) और जम्मू-कश्मीर सरकार का संयुक्त उद्यम है। इसकी अनुमानित लागत 3,700 करोड़ रुपये है और निर्माण का कार्य मेघा इंजीनियरिंग

एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MEIL) को दिया गया है। पुलिस जांच के अनुसार, यह मामला 1 नवंबर का है, लेकिन जानकारी हाल ही में सार्वजनिक हुई। प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूरों का वेरिफिकेशन किया गया तो यह खुलासा हुआ कि 29 कर्मचारियों में से पांच मजदूर ऐसे हैं जिनके परिवार के सदस्य सक्रिय या सरेंडर आतंकवादी रह चुके हैं। इनमें से एक मजदूर का चाचा हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी मोहम्मद अमीन है। दो अन्य मजदूरों का भाई भी इसी आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है। एक अन्य कर्मचारी के पिता पहले आतंकी रह चुके हैं, हालांकि उन्होंने सरेंडर कर लिया है। एक मजदूर के पिता ओवर ग्राउंड वर्कर के रूप में पहचाने गए। बाकी 24 कर्मचारियों के खिलाफ विभिन्न क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद हैं।

इस खुलासे के बाद किश्तवाड़ के एसएसपी नरेश सिंह ने मेघा इंजीनियरिंग के मैनेजर को पत्र लिखकर गंभीर चिंता व्यक्त की। पत्र में कहा गया कि रतले हाइड्रो प्रोजेक्ट राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रोजेक्ट्स हमेशा दुश्मन देशों के निशाने पर रहते हैं। ऐसे में संदिग्ध मजदूरों की भर्ती पर पुनर्विचार करना जरूरी है।

मेघा इंजीनियरिंग की तरफ से जवाब में कहा गया कि मजदूरों को हटाना फिलहाल मुश्किल है क्योंकि ये खुद आतंकवादी नहीं हैं और उनके खिलाफ किसी आपराधिक मामले में दोष सिद्ध नहीं हुआ है। हालांकि कंपनी ने आश्वासन दिया कि इन कर्मचारियों की गतिविधियों की सख्ती से निगरानी की जाएगी और किसी भी संदिग्ध स्थिति को तुरंत रिपोर्ट किया जाएगा।

इस मामले ने जम्मू-कश्मीर में विकास परियोजनाओं की सुरक्षा के मुद्दे को एक बार फिर उजागर किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे महत्वपूर्ण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को केवल तकनीकी और वित्तीय दृष्टि से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी लगातार मॉनिटर किया जाना चाहिए। इस घटना ने यह भी संकेत दिया है कि आतंकवादी संगठनों द्वारा विकास परियोजनाओं में शामिल कर्मचारियों के माध्यम से संभावित खतरा उत्पन्न करने की कोशिश की जा सकती है, इसलिए सुरक्षा मानकों को और कड़ा करने की आवश्यकता है।

मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर 36 पूर्व जजों का ऐतिहासिक समर्थन

चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ हाल ही में पेश किए गए महाभियोग प्रस्ताव को लेकर देश के न्यायिक जगत में बड़ा विवाद पैदा हो गया है। जस्टिस स्वामीनाथन के समर्थन में 36 पूर्व जजों ने खुले पत्र के माध्यम से महाभियोग प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। इससे पहले 56 पूर्व जजों ने भी इस कदम की निंदा की थी। इस कदम को न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला और लोकतंत्र के लिए खतरा बताया जा रहा है।

खुले पत्र में पूर्व जजों ने कहा कि महाभियोग प्रस्ताव का कदम जजों पर राजनीतिक और वैचारिक दबाव बनाने और उन्हें डराने की कोशिश है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि इस तरह की कोशिशों को आगे बढ़ने दिया गया, तो यह सीधे लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जड़ों पर हमला होगा। पत्र में उल्लेख किया गया कि लोकतंत्र में फैसलों की परीक्षा केवल अपील और कानूनी समीक्षा के माध्यम से होती है, न कि महाभियोग जैसी धमकियों और राजनीतिक दबाव से।

मामले की पृष्ठभूमि यह है कि जस्टिस स्वामीनाथन ने 1 दिसंबर को मंदिर और दरगाह से जुड़े विवादित मामले में हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया था। इसके कुछ ही दिनों बाद, 9 दिसंबर को प्रियंका गांधी वाड्रा समेत इंडिया गठबंधन के 107 सांसदों ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया। सांसदों का आरोप था कि जस्टिस स्वामीनाथन का फैसला पक्षपातपूर्ण और संवैधानिक दृष्टि से अनुचित था।

पूर्व जजों ने अपने पत्र में यह भी कहा कि यदि महाभियोग का रास्ता अपनाया गया तो यह जजों की स्वतंत्रता और न्यायिक निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका का कार्य केवल संवैधानिक और कानूनी दायरे में ही होना चाहिए, न कि राजनीतिक दबाव या धमकियों के अधीन।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में पूर्व जजों का ऐतिहासिक समर्थन न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संवैधानिक व्यवस्था के प्रति गंभीर संदेश है। इससे यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका पर राजनीतिक हस्तक्षेप को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों की रक्षा की जाएगी।

इस घटना ने पूरे देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और महाभियोग जैसी संवैधानिक प्रक्रियाओं के उपयोग पर बहस शुरू कर दी है। राजनीतिक गलियारों में अब यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या सांसदों द्वारा महाभियोग का इस्तेमाल न्यायिक फैसलों पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है या यह सचमुच किसी संवैधानिक उल्लंघन पर आधारित है।

इस मामले की समीक्षा और बहस देश की न्यायिक और राजनीतिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है, क्योंकि यह तय करेगा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और राजनीतिक हस्तक्षेप के बीच संतुलन कैसे रखा जाएगा।

सरकारी स्कूलों में तकनीक की नई उड़ान, कर्नाटक में 'विजयपथ' एआई लैब की शुरुआत से बदलेगा शिक्षा का भविष्य

हम्पी। कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में आधुनिक तकनीकी शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 'विजयपथ' एआई लैब का शुभारंभ किया। इस महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत होसपेटे तालुका के एक सरकारी बालिका विद्यालय से की गई, जिससे यह संदेश भी दिया गया कि तकनीकी शिक्षा का लाभ समाज के हर वर्ग, विशेषकर छात्राओं तक समान रूप से पहुंचे। इस पहल के जरिए सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को कृत्रिम मेधा, एसटीईएम और रोबोटिक्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से परिचित कराया जाएगा।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह परियोजना पायलट चरण में शुरू की गई है, जिसके तहत पांच अत्याधुनिक एआई, एसटीईएम और रोबोटिक्स लैब स्थापित की जा रही हैं। इन लैब्स में हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटर, एआई के अनुकूल सॉफ्टवेयर, रोबोटिक्स किट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़े उपकरण, विभिन्न प्रकार के सेंसर और सुरक्षित ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य छात्रों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित न रखकर उन्हें व्यावहारिक अनुभव देना है, ताकि वे भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस अवसर पर कहा कि आज के दौर में तकनीक केवल सुविधा नहीं, बल्कि अवसर का माध्यम बन चुकी है। अगर सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को शुरू से ही एआई और डिजिटल स्किल्स से जोड़ा जाए, तो वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पीछे नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह पहल नई शिक्षा नीति 2020, डिजिटल इंडिया और प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत 2047' के विजन के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर और तकनीकी सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है।

'विजयपथ' परियोजना के तहत 2,000 से अधिक छात्रों को एआई, कोडिंग, रोबोटिक्स और डिजिटल इनोवेशन से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही 200 से अधिक शिक्षकों को भी विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ताकि वे आधुनिक तकनीकों को समझकर विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से मार्गदर्शन दे सकें। इससे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का तरीका अधिक इंटरैक्टिव और भविष्य उन्मुख बनेगा।

इस पहल को एक स्केलेबल कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल के रूप में देखा जा रहा है, जिसे आगे चलकर राज्य के अन्य जिलों और स्कूलों तक भी विस्तारित किया जा सकता है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि 'विजयपथ' जैसी परियोजनाएं सरकारी शिक्षा व्यवस्था की छवि बदलने में अहम भूमिका निभा सकती हैं और ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों के छात्रों को भी तकनीकी दुनिया से जोड़ सकती हैं।

कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में 'विजयपथ' एआई लैब की शुरुआत न केवल शिक्षा के क्षेत्र में एक नवाचार है, बल्कि यह उस सोच का प्रतीक भी है जिसमें सरकारी स्कूलों के छात्रों को भी वही अवसर और संसाधन देने का प्रयास किया जा रहा है, जो अब तक केवल निजी और महंगे संस्थानों तक सीमित थे। यह पहल आने वाले वर्षों में छात्रों के करियर, कौशल विकास और डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है।

आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को विश्व बैंक की बड़ी राहत, 70 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता को मंजूरी

इस्लामाबाद। गंभीर आर्थिक संकट और लगातार बिगड़ती वित्तीय स्थिति से गुजर रहे पाकिस्तान को विश्व बैंक से बड़ी राहत मिली है। शनिवार को विश्व बैंक ने पाकिस्तान को 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करने की मंजूरी दे दी। यह मदद देश की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने, सरकारी वित्त को मजबूत करने और सेवा क्षेत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से दी जा रही है। पाकिस्तान के संकेतों के अनुसार, यह सहायता ऐसे समय पर आई है जब देश भारी कर्ज, महंगाई और राजकोषीय दबावों से जूझ रहा है।

विश्व बैंक की यह सहायता समावेशी विकास के लिए सार्वजनिक संसाधन कार्यक्रम (PRID-MPA) के तहत दी जाएगी। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आने वाले समय में विश्व बैंक पाकिस्तान को कुल 1.35 अरब डॉलर तक का वित्तपोषण भी उपलब्ध करा सकता है। इसमें से लगभग 600 मिलियन डॉलर संघीय स्तर की योजनाओं पर खर्च किए जाएंगे, जबकि 100 मिलियन डॉलर सिंध प्रांत के लिए निर्धारित किए गए हैं। इससे पहले अगस्त महीने में विश्व बैंक ने पंजाब प्रांत में प्राथमिक शिक्षा सुधार के लिए 47.9 मिलियन डॉलर का अनुदान भी दिया था, जिसे आर्थिक सुधारों की दिशा में एक अहम कदम माना गया था।

विश्व बैंक के पाकिस्तान कंट्री डायरेक्टर बोलोरमा अमगाबाजार ने इस वित्तीय सहायता को पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य पाकिस्तान को समावेशी और टिकाऊ विकास के लिए अधिक संसाधन जुटाने में मदद करना है, ताकि इन संसाधनों का उपयोग कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्यक्रम के तहत स्कूलों और स्वास्थ्य क्लीनिकों के लिए वित्तपोषण बढ़ाया जाएगा, एक निष्पक्ष और प्रभावी कर प्रणाली को लागू करने में सहयोग किया जाएगा और सामाजिक तथा जलवायु से जुड़े निवेशों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

विश्व बैंक के पाकिस्तान के लिए प्रमुख अर्थशास्त्री तोबियास अख्तर हक ने कहा कि यह वित्तीय सहायता देश की कमजोर होती राजकोषीय नींव को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। उनके अनुसार, इस मदद से मानव पूंजी के विकास, जलवायु लचीलापन बढ़ाने और सरकारी संसाधनों को सीधे आम जनता तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान को दी जा रही यह सहायता केवल तात्कालिक राहत नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक सुधारों और सामाजिक विकास की दिशा में एक जरूरी निवेश है।

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि विश्व बैंक की यह मंजूरी पाकिस्तान के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि सरकार इन संसाधनों का उपयोग सही दिशा में करे। यदि पारदर्शिता और सुधारों पर सही तरीके से अमल नहीं हुआ, तो यह सहायता भी स्थायी समाधान साबित नहीं होगी। फिलहाल, विश्व बैंक की यह वित्तीय मदद पाकिस्तान को आर्थिक अस्थिरता के दौर से उबरने के लिए एक अहम सहारा मानी जा रही है।

संपादकीय

जिम्मेदार व्यवहार रोकेगा रोड एक्सीडेंट

लोकसभा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का वह बयान तार्किक ही है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में अधिकतर सड़क दुर्घटनाएं मानवीय व्यवहार से जुड़ी हैं। निश्चय ही यदि वाहन चालकों को सड़क व्यवहार के प्रति जागरूक किया जाए और हम जिम्मेदारी-सावधानी से वाहन चलाएं तो हर साल हजारों जिंदगियां बचायी जा सकती हैं। भारत में दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले कम वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं, लेकिन सड़क हादसों के मामले में हम अव्वल हैं। विडंबना देखिए कि एक साल में देश के भीतर करीब पांच लाख सड़क हादसे दर्ज किए जाते हैं। बड़ी संख्या उन हादसों की भी है जो छोटे शहरों व भीतरी इलाकों में होते तो हैं, लेकिन दर्ज नहीं होते। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देश में हर साल करीब 1.8 लाख लोग इन हादसों में मारे जाते हैं। लाखों लोग इन हादसों में घायल होते हैं। हजारों लोग ऐसे भी होते हैं जो हादसों के बाद जीवनपर्यंत सामान्य जीवन नहीं जी पाते हैं। दुखद स्थिति यह भी है कि मरने वालों में सर्वाधिक संख्या युवाओं की होती है। एक आंकड़े के अनुसार मरने वालों में 66 फीसदी लोग 18 से 34 साल के बीच होते हैं। जो अपने परिवार के कमाने वाले व्यक्ति होते हैं। फलतः हादसे के बाद कई परिवार गरीबी के दलदल में धंस जाते हैं। दरअसल, सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण तेज गति से वाहन चलाना भी है। सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि ओवर स्पीडिंग से 68 फीसदी से अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। वहीं निर्धारित स्पीड से अधिक तेजी से वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं के चलते ही 68 फीसदी मौतें भी होती हैं। निश्चित रूप से ये हादसे व मौतें मानवीय व्यवहार की कमजोरी से जुड़े हैं। जहां देश में राष्ट्रीय राजमार्गों व एक्सप्रेस-वे का तेजी से विस्तार हुआ है तो बेहतर सड़कों में वाहन चालकों की गति अनियंत्रित हो चली है। जो कालांतर सड़क हादसों की वजह बनती है।

यह विडंबना है कि हम अकसर सुरक्षा नियमों की अनदेखी करते हैं। आज की युवा पीढ़ी हेलमेट पहनने से परहेज करती है। यह जानते हुए कि हादसों में सिर की चोट जानलेवा बन जाती है। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में हेलमेट न लगाने के कारण 54,568 लोगों की मौत हुई। वहीं सीट बेल्ट न लगाने से 16 हजार से अधिक यात्रियों की जान गई। इन हादसों की एक बड़ी वजह ऐसे अकुशल चालकों का होना भी था, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं था। आंकड़ों के अनुसार दुर्घटनाओं के लिये जिम्मेदार चालकों में 33,827 ऐसे थे जिनके पास लाइसेंस नहीं थे। देश में बड़ी संख्या ऐसे चालकों की होती है, जो मेडिकली फिट नहीं होते। इसके अलावा जुगाड़ से ले-देकर लाइसेंस बनाने वालों की भी कमी नहीं है। वे वाहन चलाने की पर्याप्त योग्यता व अनुभव के बिना ही चालक बन बैठते हैं। हाल के वर्षों में नशे की हालात में वाहन चलाने का फैशन भी बना है। कई हादसों के बाद खुलासा हुआ कि फलां चालक नशे में धुत था। हालांकि, महानगरों व शहरों में नाका लगाकर शराब पीकर वाहन चलाने वालों की पकड़-धकड़ की जाती है। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्गों व एक्सप्रेस-वे पर ऐसी जांच बड़े पैमाने पर होती नजर नहीं आती। वहीं ऐसे चालकों की भी कमी नहीं है, जो फोन पर बात करते हुए वाहन चलाते हैं। जिससे लगातार दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। निश्चित रूप से फोन पर बातचीत करता व्यक्ति भावावेश में उद्वेलित हो सकता है, जिससे वाहन चलाने की गुणवत्ता बाधित होती है। वाहन को सुरक्षित ढंग से चलाना भी एक कला है। चालक का मानसिक रूप से शांत होना भी जरूरी है। हाल के दिनों में सड़कों की बेहतर स्थितियों में लोगों में रात में सफर करने का रुझान बढ़ा है। गाहे-बगाहे चालक को झपकी लगने पर दुर्घटना होने के समाचार अकसर सुनने में आते हैं। निश्चित रूप से सड़क हादसों के मूल में तकनीकी कारण और सड़कों के डिजाइन व गुणवत्ता की भी भूमिका होती है। लेकिन हमारी नियंत्रित गति, सावधानी व सजगता दुर्घटनाएं टाल भी सकती है।

भारत के Halal Certification को Oman की मंजूरी आस्था का धंधा करने वालों का खेल होगा खत्म

> “अब तक समस्या यह थी कि मुस्लिम देशों में खासकर खाड़ी बाज़ारों में, हलाल प्रमाणन के बिना भारतीय मांस और खाद्य उत्पाद बेचना लगभग नामुमकिन था। इस मजबूरी का फायदा उठाकर वही निजी संगठन निर्यातकों की गर्दन पर सवार रहे।

देश-विदेश में वर्षों से हलाल सर्टिफिकेशन एक संगठित धंधा बन चुका है। कुछ निजी संस्थाएँ खुद को 'धर्म का ठेकेदार' घोषित कर मोटी फ़ीस के बदले हलाल सर्टिफिकेट जारी करती हैं वह भी बिना किसी सरकारी निगरानी, बिना पारदर्शिता और बिना जवाबदेही के। इन्हीं संस्थाओं को लेकर बार-बार यह गंभीर सवाल उठते रहे हैं कि उनके पास इकट्ठा हुआ पैसा आखिर जाता कहाँ है। जाँच एजेंसियों और सुरक्षा विशेषज्ञों ने भी आगाह किया है कि जब पैसा बिना नियंत्रण के बहे, तो वह टैरर फंडिंग जैसे खतरनाक रास्तों पर भी जा सकता है।समस्या यह थी कि मुस्लिम देशों में खासकर खाड़ी बाज़ारों में, हलाल प्रमाणन के बिना भारतीय मांस और खाद्य उत्पाद बेचना लगभग नामुमकिन था। इस मजबूरी का फायदा उठाकर वही निजी संगठन निर्यातकों की गर्दन पर सवार रहे। सर्टिफिकेट चाहिए तो उनकी शर्तें मानो, उनकी कीमत दो, उनकी व्यवस्था स्वीकार करो, चाहे वह कितनी ही अपारदर्शी क्यों न हो। सरकार की गैरमौजूदगी में यह समानांतर सत्ता वर्षों तक फलती-फूलती रही। लेकिन अब इस खेल पर ब्रेक लगने लगा है। भारत सरकार ने आधिकारिक, सरकार-मान्य और अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य हलाल प्रमाणन को लागू कर उस पूरे नेटवर्क की जड़ पर चोट की है, जो आस्था की आड़ में कारोबार और संभावित रूप से आतंकी फंडिंग का रास्ता खोलता रहा। ओमान द्वारा भारत के सरकारी हलाल सर्टिफिकेट को मान्यता दिया जाना सिर्फ़ निर्यातकों के लिए राहत नहीं है, यह उस अनियंत्रित सिस्टम के खिलाफ सीधी

कार्रवाई है, जिसे अब तक कोई छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यह कदम साफ़ संदेश देता है कि आस्था का सम्मान होगा, लेकिन आस्था के नाम पर लूट, दलाली और संदिग्ध फंडिंग अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम आपको बता दें कि भारत ने अपने निर्यात हितों को साधने और वैश्विक बाज़ार में धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप व्यापार को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया है कि भारत उन सभी देशों से मिशन मोड में संवाद कर रहा है, जहाँ मांस और मांस उत्पादों के निर्यात के लिए हलाल प्रमाणन अनिवार्य है। इस कड़ी में ओमान के साथ हाल ही में हस्ताक्षरित भारत–ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) एक अहम मील का पत्थर साबित हुआ है।

पीयूष गोयल ने बताया है कि ओमान पहला ऐसा देश बन गया है जिसने आधिकारिक रूप से भारत के हलाल मांस प्रमाणन को मान्यता दी है। हम आपको बता दें कि इससे पहले खाड़ी देशों और अन्य इस्लामिक देशों में हलाल प्रमाणन के नाम पर अनौपचारिक और अपारदर्शी प्रक्रियाएँ चल रही थीं। भारत पिछले तीन–चार वर्षों से प्रयास कर रहा था कि इन देशों को औपचारिक और सरकार स्वीकृत हलाल प्रमाणन प्रणाली अपनाने के लिए राज़ी किया जाए। इस समझौते के तहत ओमान भारत के हलाल प्रमाणन को सीधे स्वीकार करेगा, जिससे दोहराव वाली जाँच, अतिरिक्त प्रमाणन और अनावश्यक लागत से भारतीय निर्यातकों को राहत मिलेगी। इससे न केवल निर्यात लागत घटेगी, बल्कि भारतीय उत्पादों की बाज़ार तक पहुँच भी तेज़ और आसान होगी। पीयूष गोयल ने साफ शब्दों में कहा कि भारत अब सभी 55 इस्लामिक देशों के साथ इसी तरह की व्यवस्था लागू कराने के लिए सक्रिय बातचीत करेगा। देखा जाये तो भारत ने अब साफ कर दिया है कि धार्मिक मान्यताओं का सम्मान होगा, लेकिन अव्यवस्था और दलाली की कीमत पर नहीं। औपचारिक और प्रक्रिया आधारित हलाल प्रमाणन की बात दरअसल भारत के उस इरादे का संकेत है, जिसमें वह आस्था को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ जोड़ना चाहता है। यह उन तमाम आलोचकों के लिए भी जवाब है, जो हलाल को लेकर या तो अंध-विरोध करते हैं या फिर आंख मूंदकर उसका समर्थन करते हैं।

आर्थिक दृष्टि से देखें तो खाड़ी और इस्लामिक देश भारत के लिए कोई मामूली बाज़ार नहीं हैं। मांस, खाद्य प्रसंस्करण और ऑर्गेनिक उत्पादों में ये देश बड़े आयातक हैं। यदि भारत अपने प्रमाणन को इन बाज़ारों में मान्य करा लेता है, तो यह सिर्फ़ निर्यात बढ़ाने का मामला नहीं होगा, यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की साख मज़बूत करने का मामला होगा।

सबसे अहम बात यह है कि यह पहल भारत को 'रिएक्टिव' से 'प्रोएक्टिव' बना रही है। अब भारत दूसरों के बनाए नियमों को चुपचाप स्वीकार करने वाला देश नहीं, बल्कि अपने मानकों को आत्मविश्वास से पेश करने वाला खिलाड़ी बन रहा है। हलाल प्रमाणन का यह कदम दरअसल एक बड़े संदेश का हिस्सा है यानि भारत अब वैश्विक व्यापार में बराबरी से बात करेगा, न झुकेगा, न हिचकेगा। बहरहाल, असली परीक्षा तब होगी जब भारत बाकी 54 इस्लामिक देशों में भी इसी तरह की औपचारिक मान्यता हासिल करेगा। तब यह कहा जा सकेगा कि भारत ने न सिर्फ़ व्यापार जीता, बल्कि व्यवस्था भी।

प्रेरणा

एक अनदेखी भूल की गूंज, जिसने शांति से बसे साम्राज्य को विनाश की आग में झोंक दिया

बहुत समय पहले एक समृद्ध और सुव्यवस्थित राज्य हुआ करता था, जिसके शासक थे राजा अनंतदेव। उनका राज्य दूर-दूर तक सुख, शांति और अनुशासन के लिए जाना जाता था। प्रजा संतुष्ट थी, राजकोष भरा हुआ था और राजमहल वैभव तथा व्यवस्था का प्रतीक माना जाता था। राजा स्वयं को एक कुशल प्रशासक समझते थे और उन्हें विश्वास था कि उनके राज्य में कोई भी अव्यवस्था पनप ही नहीं सकती। किंतु नियति अक्सर सबसे छोटी चूक को ही सबसे बड़ा सबक बना देती है।

एक दिन राजा अनंतदेव अपने निजी कक्ष में भोजन कर रहे थे। सोने-चांदी के बर्तनों में सजे व्यंजन उनके सामने रखे थे। भोजन के दौरान उन्होंने शहद का पात्र उठाया। उसी क्षण उनके हाथ से शहद की एक छोटी-सी बूंद फिसलकर चमकदार संगमरमर के फर्श पर गिर पड़ी। राजा की दृष्टि उस पर गई, पर उनके मन में यह विचार आया कि इतनी छोटी बात पर ध्यान देना राजा की गरिमा के अनुकूल नहीं। उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर में कोई नौकर आएगा और स्वयं ही उसे साफ कर देगा। यह सोचकर उन्होंने न तो किसी को बुलाया और न ही स्वयं उस बूंद को हटाने का प्रयास किया। यही वह क्षण था, जहां से घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू हुई, जिसका अंत विनाश में हुआ।

कुछ समय बाद एक नौकर वहां आया। वह अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसकी नजर फर्श पर पड़ी उस शहद की बूंद पर नहीं गई। वह बिना कुछ देखे अपना काम निपटाकर चला गया। शहद वहीं पड़ा रहा। धीरे-धीरे उसकी मिठास की सुगंध फैलने लगी और आसपास से मक्खियां वहां आने लगीं। पहले कुछ मक्खियां आईं, फिर उनकी संख्या बढ़ती चली गई। फर्श पर मक्खियों की भनभनाहट होने लगी, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।

दीवार के कोने में छिपी एक छिपकली की नजर उन मक्खियों पर पड़ी। उसे भोजन का अवसर दिखाई दिया और वह धीरे-धीरे नीचे उतर आई। वह मक्खियों को पकड़ने लगी, जिससे वहां हलचल बढ़ गई। उसी समय राजमहल में पली-बढ़ी एक बिल्ली की नजर उस छिपकली पर पड़ी। शिकार की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर वह छिपकली को पकड़ने के लिए झपटी। बिल्ली और छिपकली की इस आपाधापी में शोर मच गया और चीजें इधर-उधर गिरने लगीं।

इस शोर को सुनकर संयोगवश राजमहल के बाहर बगीचे में घूम रहे कुछ कुत्ते भीतर आ गए। उन्होंने बिल्ली को देखा और उसे अपना शत्रु समझकर उस पर टूट पड़े। बिल्ली किसी तरह फुर्ती से जान बचाकर भाग गई, लेकिन कुत्ते आपस में ही भिड़ गए। भौंकने, दहाड़ने और लड़ने की आवाज़ से पूरा महल गूंज उठा। कई कुत्ते घायल हो गए और उनका खून बहने लगा।

जब यह समाचार कुत्तों के मालिकों तक पहुंचा, तो वे गुस्से में राजमहल की ओर दौड़ पड़े। हर मालिक अपने कुत्ते को निर्दोष बताने लगा और दूसरे पर दोष मढ़ने लगा। पहले बहस हुई, फिर बहस ने कटु रूप लिया और देखते ही देखते हाथापाई शुरू हो गई। वहां इकट्ठा हुई भीड़ में उत्तेजना फैल गई। कुछ शरारती और असामाजिक तत्वों ने इस अफरातफरी को अवसर में बदल लिया। उन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। महल के द्वार तोड़े गए, कीमती वस्तुएं लूटी गईं और अंततः राजमहल के एक हिस्से में आग लगा दी गई। जो राज्य कभी शांति और समृद्धि का प्रतीक था, वह कुछ ही समय में अराजकता और भय का केंद्र बन गया।

काफी देर बाद सैनिकों और अधिकारियों ने स्थिति पर काबू पाया। आग बुझाई गई, भीड़ को तितर-बितर किया गया और शांति स्थापित करने का प्रयास किया गया। जब राजा अनंतदेव ने इस भयानक उपद्रव का कारण जानना चाहा, तो मंत्रियों को जांच का आदेश दिया गया। मंत्री ने घटनाओं की कड़ियों को जोड़ा और अंत में सत्य राजा के सामने रखा। उसने विनम्रता से बताया कि महाराज, इस पूरे विनाश की जड़ वह शहद की छोटी-सी बूंद है, जिसे भोजन के समय साफ नहीं किया गया। यदि उसी क्षण उस छोटी-सी असावधानी को ठीक कर लिया गया होता, तो इतनी बड़ी आपदा कभी जन्म नहीं लेती।

यह सुनकर राजा अनंतदेव का हृदय पश्चाताप से भर गया। उन्हें पहली बार यह अहसास हुआ कि सत्ता और वैभव के बावजूद वे भी एक छोटी-सी लापरवाही के दोषी हैं। उन्होंने समझ लिया कि समस्याएं जब छोटी होती हैं, तभी उन्हें सुलझा लेना चाहिए। उसी दिन राजा ने यह प्रण लिया कि राज्य में किसी भी छोटी गलती या अव्यवस्था को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और प्रजा को भी यही शिक्षा दी जाएगी।

यह कथा हमें यह गहरा संदेश देती है कि जीवन में छोटी-सी अनदेखी भूल भी समय के साथ भयावह रूप ले सकती है। जो समस्या आज मामूली लगती है, वही कल बड़े संकट का कारण बन सकती है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हर छोटी चूक को समय रहते संभाल लिया जाए, क्योंकि एक बूंद से उठा तूफान पूरे जीवन या पूरे राज्य को तबाह कर सकता है।

फडणवीस कैबिनेट में पाब्लो एस्कोबार

एकनाथ शिंदे भ्रष्टाचार के पैसों से राजनीति कर रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। यह सच है कि विधायक और नगरसेवक खरीदे जा रहे हैं, लेकिन क्या इसमें 'ड्रग्स' यानी नशीले पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धन का हाथ भी है? यह सवाल महाराष्ट्र की जनता के मन में है। महाराष्ट्र बड़े पैमाने पर नशा और नशीले पदार्थों की चपेट में है। जगह-जगहों पर नशीले पदार्थों का जखीरा मिल रहा है, लेकिन आठ दिन पहले पुलिस ने सातारा के सावरी गांव में एक शेड से कम से कम १५० करोड़ रुपए की कोकीन जब्त की। इसके बाद सातारा के पंचगनी में ७५ करोड़ रुपए की कोकीन जब्त की गई। ऐसा लगता है मानो सातारा कोकीन की राजधानी ही बन गया है। सातारा के सावरी गांव में जिस जगह से १५० करोड़ रुपए की कोकीन जब्त की गई, वह उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र में अमित शाह के एजेंट शिंदे के भाई की है। शेड के बगल में 'तेजयश' रिसॉर्ट है, जिसके मालिक प्रकाश शिंदे हैं। उप मुख्यमंत्री शिंदे-मिंधे का हेलिकॉप्टर महीने में कम से कम पांच से दस बार सावरी के पास दारे गांव में उतरता है। कहा जाता है कि शिंदे यहां आकर खेती करते हैं और उससे उनकी आमदनी होती है। अगर शिंदे को खेती से इतनी आमदनी हो रही है तो महाराष्ट्र के हजारों किसानों को आत्महत्या करने और साहूकारों का कर्ज चुकाने के लिए अपनी किडनी बेचने की नौबत क्यों आ रही है? इसलिए शिंदे और उनका परिवार किस तरह की खेती करते हैं उसका खुलासा हो गया है? शिंदे परिवार के घर के पीछे कोकीन की फैक्ट्री मिली। विश्व बाजार में कोकीन की कीमत सोने से भी ज्यादा है। अगर राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके मौजूदा उप मुख्यमंत्री को यह नहीं पता कि उनके दारा-सावरी गांव में सालों से नशीले पदार्थों का धंधा फल-फूल रहा है तो वे नंबर एक 'समझदार' हैं। जब पंजाब जैसा राज्य पूरी तरह से नशे का आदी हो गया था, तब उसे 'उड़ता पंजाब' कहा गया था। जब गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए की नशीले पदार्थों की खेप जब्त की गई थी तब लगा। ड्रग्स की खेप अफगानिस्तान होते हुए गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर सुरक्षित पहुंचती है और महाराष्ट्र समेत पूरे देश में वितरित की जाती है। नासिक, पुणे और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में अभिभावकों ने 'ड्रग्स' के खिलाफ मोर्चे निकाले। नासिक और अन्य जगहों पर 'ड्रग्स' बनानेवाली फैक्ट्रियों को ध्वस्त कर दिया गया। फिर भी महाराष्ट्र के स्कूलों और कॉलेजों में ड्रग्स प्रचुर मात्रा में मिल रहे हैं और युवा पीढ़ी इसमें बर्बाद हो रही है, क्योंकि पुणे और सातारा में मंत्रियों के संरक्षण में ड्रग्स फैक्ट्रियां बेरोकटोक चल रही हैं। मंत्रालय से सातारा ड्रग मामले में उप मुख्यमंत्री के भाई प्रकाश शिंदे को बचाने की कोशिश की गई। उप मुख्यमंत्री कार्यालय ने सातारा के पुलिस अधीक्षक तुषार दोशी को बार-बार फोन किया। प्रकाश शिंदे का नाम एफआईआर में आने से रोकने के लिए दबाव डाला गया। मुंढवा भूमि घोटाले में भी उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के चिरंजीव पार्थ को इसी तरह सुरक्षित निकाला गया। पार्थ के शरीर पर कानून का एक भी निशान नहीं लगने दिया गया और अब फडणवीस के गृह विभाग ने उप मुख्यमंत्री शिंदे के भाई को 'ड्रग्स' के मामले में बचा लिया है। महाराष्ट्र को ड्रग्स के चंगुल में धकेलने वाले इस मामले पर मुख्यमंत्री फडणवीस और उनके वाचाल लोग चुप क्यों हैं? और वक्त मिंधे गुट के प्रवक्ता बेतुकी बातें करते हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री के भाई के ड्रग्स के मामले में ये सभी लोग उसी 'ड्रग्स' को चाटकर गाफिल पड़े हुए हैं। सातारा स्थित ड्रग्स फैक्ट्री में काम करने के लिए पश्चिम बंगाल से ५०-६० मजदूरों को लाया गया था। इन लोगों के बांग्लादेशी घुसपैठिए होने का संदेह है। अगर यह सच है तो कहा जा सकता है कि 'मिंधे' ने हिंदुत्व की अच्छी सेवा जारी रखी है और इसके लिए 'मालिक' अमित शाह को मिंधे को 'हिंदू ड्रग्स भूषण' की उपाधि देकर सम्मानित करना चाहिए। इस मामले में पुणे में अजीत पवार की पार्टी के पदाधिकारी विशाल मोरे को गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य संदिग्ध आरोपी, ओमकार दिघे के प्रकाश शिंदे से घनिष्ठ संबंध हैं। जब पुलिस जांच में पता चला कि इस ड्रग्स फैक्ट्री के प्रकाश शिंदे के 'तेजयश' होटल से चलाए जा रहे थे तो जांच अधिकारी आत्माजी सावंत को श्रीकांत शिंदे के जरिए धमकाया गया और प्रकाश शिंदे को बचा लिया गया। प्रकाश शिंदे, ओमकार दिघे और विशाल मोरे मिलकर सावरी गांव में एक 'ड्रग रैकेट' चला रहे थे। जब उनके संबंध मुंबई और पुणे तक फैल गए तो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच सातारा गई और कार्रवाई की। तब तक सातारा के पुलिस अधीक्षक मिंध्या की चाकरी में व्यस्त थे। जब यह महसूस हुआ कि मुंबई पुलिस सातारा ऑपरेशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है तो सातारा के पुलिस अधीक्षक तुषार दोशी को वहां भेजा गया और मूल जांच में बाधा डाली गई। यह वही तुषार हैं, जिन्होंने जालना एसपी रहते हुए अंतरवाली में मराठा आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज करके महाराष्ट्र में आग लगा दी थी। इसके 'इनाम' के तौर पर तुषार दोशी को 'सातारा' का विशेष प्रभार दिया गया था। उनकी नाक के नीचे ही एक 'ड्रग' फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस अधीक्षक और उनकी पुलिस फोर्स मिंधे के गांव में सैकड़ों बार जा चुकी है, लेकिन पुलिस को शिंदे के खेत-खलिहान की 'ड्रग' फैक्ट्री नहीं दिखाई पड़ी। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों के पुणे और सातारा जिले आस-पास हैं। इन दोनों जिलों में ड्रग माफिया, लैंड माफिया, गैंगवॉर और महिलाओं पर अत्याचार जैसे अपराधों ने तांडव मचा रखा है। फडणवीस इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। क्या उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज्य के पाब्लो एस्कोबार हैं? यह सवाल कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने पूछा है। पाब्लो, जिसने ड्रग्स व्यापार से सत्ता और धन कमाया और अय्याशी की, उसी धन से राजनीति करनेवाला, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया था।

अभियान

जहां पत्थर नहीं, श्रद्धा बोलती है-स्वर्णगिरि धाम में साक्षात वेंकटेश्वर की अनुभूति

तेलंगाना की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धरती पर स्थित स्वर्णगिरी वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर एक ऐसा तीर्थ है, जहां कदम रखते ही श्रद्धालु को तिरुमला जैसा भाव अनुभव होने लगता है। भुवनगिरी क्षेत्र की मानेपल्ली पहाड़ियों पर बना यह भव्य मंदिर केवल पत्थरों और शिल्प का निर्माण नहीं, बल्कि गहरी आस्था, अटूट विश्वास और ईश्वर की कृपा की जीवंत कहानी है। हैदराबाद से लगभग सैंतालीस किलोमीटर दूर फैला यह विशाल मंदिर परिसर बाइस एकड़ भूमि में विस्तृत है और जिस पहाड़ी पर इसका निर्माण हुआ है, उसे स्वर्णगिरि नाम देकर इसे एक पवित्र पहचान दी गई है।

दूर से दिखाई देने वाले विशाल राजगोपुरम श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जैसे-जैसे भक्त मंदिर के समीप पहुंचता है, वातावरण में दिव्यता घुलती चली जाती है। मंदिर की वास्तुकला में विजयनगर, पल्लव, चोल और चालुक्य काल की शिल्प परंपराओं का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। विशाल मंडप, नक्काशीदार स्तंभ, चौड़े प्रांगण और गर्भगृह के ऊपर बना पांच मंजिला विमान गोपुरम इस मंदिर को दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण बनाते हैं। यह भव्य संरचना केवल देखने में ही नहीं, बल्कि अनुभव करने में भी अद्वितीय है।

मंदिर के गर्भगृह में विराजमान भगवान श्री वेंकटेश्वर की बारह फुट ऊंची प्रतिमा इस दिव्य धाम की आत्मा है। यह प्रतिमा तेलंगाना की सबसे ऊंची वेंकटेश्वर प्रतिमा मानी जाती है और इसके दर्शन मात्र से ही भक्तों के मन में श्रद्धा और शांति का भाव जागृत हो जाता है। भगवान की मुखाकृति में करुणा, नेत्रों में दिव्यता और संपूर्ण स्वरूप में अलौकिक तेज दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं भगवान स्वर्णगिरि की पहाड़ियों से अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों।

इस मंदिर की स्थापना के पीछे जुड़ी कथा इसे और भी पवित्र और भावनात्मक बनाती है। प्रसिद्ध उद्योगपति श्रीमन मानेपल्ली रामाराव के जीवन में आया वह कठिन समय, जब उनकी पत्नी श्रीमति विजयलक्ष्मी एक गंभीर दुर्घटना के बाद कोमा में चली गई थीं, परिवार के लिए असहनीय पीड़ा लेकर आया। चिकित्सकों ने जब आशा छोड़ दी, तब परिवार ने भगवान वेंकटेश्वर की शरण ली। तिरुपति का पवित्र जल उन्हें पिलाया गया और इसके बाद जो हुआ, वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। धीरे-धीरे उनकी हालत में सुधार हुआ और जीवन लौट आया। इस दिव्य कृपा से अभिभूत होकर परिवार ने भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए एक भव्य मंदिर निर्माण का संकल्प लिया।

यही संकल्प आगे चलकर स्वर्णगिरी वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के रूप में साकार हुआ, जिसे पूर्ण होने में सात वर्षों से अधिक का समय लगा।

मंदिर परिसर में स्थापित अन्य धार्मिक संरचनाएं भी इसकी भव्यता को और बढ़ा देती हैं। यहां स्थित एक सौ बीस फुट ऊंचा हनुमान मंडप शक्ति, भक्ति और संरक्षण का प्रतीक है। एक ही पत्थर से निर्मित चालीस फुट ऊंची हनुमान प्रतिमा शिल्पकला की अद्वितीय मिसाल प्रस्तुत करती है। इसके अलावा मंदिर में स्थापित भारत की दूसरी सबसे बड़ी कांसे की घंटी, जिसका वजन लगभग डेढ़ टन है, जब बजती है तो उसकी गूंज मानो भक्तों के हृदय तक उतर जाती है। संध्या के समय जला नारायण स्वामी सन्निधि प्रकाश से जगमगाती है और उस समय मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत, पवित्र और अलौकिक प्रतीत होता है।

यह मंदिर केवल दर्शन का स्थल नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। सुबह की आरती से लेकर रात की शेज आरती तक यहां भक्ति का निरंतर प्रवाह बना रहता है। वर्ष भर यहां भक्तों का आगमन होता है, लेकिन मानसून और शीत ऋतु में यहां की प्राकृतिक सुंदरता और भी निखर जाती है। बारिश के बाद हरियाली से आच्छादित पहाड़ियां, ठंडी हवाएं और बादलों से घिरा आकाश पूरे क्षेत्र को स्वर्ग समान बना देता है। ऐसे में मंदिर दर्शन एक आध्यात्मिक यात्रा के साथ-साथ प्रकृति से जुड़ने का भी अनुपम अवसर बन जाता है। यात्रा की दृष्टि से भी स्वर्णगिरि वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर अत्यंत सुगम है। हैदराबाद का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यहां से लगभग छिहत्तर किलोमीटर दूर है, जहां से टैक्सी द्वारा आसानी से मंदिर पहुंचा जा सकता है। रेल मार्ग से आने वाले श्रद्धालु भोंगिर या सिकंदराबाद जंक्शन तक पहुंचकर सड़क मार्ग से मंदिर जा सकते हैं। सड़क मार्ग से हैदराबाद से भुवनगिरी तक सीधी बस और निजी वाहन सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे यात्रा सरल और सुविधाजनक हो जाती है। स्वर्णगिरि वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर वास्तव में उस आस्था का प्रतीक है, जहां विश्वास चमत्कार बन जाता है और चमत्कार भक्ति का स्वरूप ले लेता है। यह मंदिर न केवल भगवान वेंकटेश्वर की महिमा का बखान करता है, बल्कि यह मानव जीवन में विश्वास, कृतज्ञता और ईश्वर की कृपा की अमर कथा भी सुनाता है। यहां आकर हर भक्त अपने मन की उलझनों से मुक्त होकर भगवान के चरणों में शांति, सुकून और दिव्यता का अनुभव करता है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

अटल नेतृत्व, अविरत विकास : सुशासन से महिला सशक्तिकरण

राज्य में लखपति दीदी तथा नमो ड्रोन दीदी योजना से महिलाएँ बनीं आत्मनिर्भर

- दो वर्ष में राज्य में लखपति दीदी की संख्या 5.96 लाख के पार, गाँव में रहने वालीं महिलाओं के सपने हो रहे हैं साकार
- कंकुबेन ने कच्छी हस्तकला उत्पादों की बिक्री से वार्षिक दस लाख रुपए से अधिक की कमाई की, अब ऑनलाइन साइट्स पर भी बिक्री
- प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में गुजरात ने नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए अनेक सफल आयाम अपनाए हैं : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

गांधीनगर : सुशासन द्वारा राज्य के नागरिकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य के साथ राज्य सरकार हमेशा प्रयासरत रही है। सुदूरवर्ती नागरिकों तक विकास पहुँचाने तथा महिलाओं को सशक्त बनाकर भारत की विकास यात्रा में जोड़ने के लिए विभिन्न पहलें की गई हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2023 में 'लखपति दीदी' योजना शुरू की गई थी। 2027 तक 3 करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का इस योजना का उद्देश्य है। गुजरात की महिलाओं को इस योजना का व्यापक लाभ मिले; इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में व्यापक प्रयास किए गए हैं। परिणामस्वरूप दिसंबर 2025 तक राज्य में लगभग 5 लाख 96 हजार महिलाओं की आय एक लाख रुपए से अधिक तक पहुँची है और वे गर्व के साथ गुजरात की 'लखपति दीदी' बनी हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा है, "प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में गुजरात ने नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए अनेक सफल आयाम अपनाए हैं। लखपति दीदी योजना के सफल क्रियान्वयन से गुजरात आगामी समय में 10 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए तैयार है।"

कच्छ की कंकुबेन गर्वा की वार्षिक आय 10 लाख रुपए से अधिक

लखपति दीदी कार्यक्रम को राज्य सरकार ने सफलतापूर्वक जमीनी स्तर पर क्रियान्वित किया है। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं के जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। कच्छ में भुज तहसील के मानकुवा गाँव में रहने वालीं कंकुबेन गर्वा का परिवार परंपरागत रूप से हस्तकला से जुड़ा हुआ है। उन्होंने 'सरस मेला' में शामिल होकर उनके कच्छी हस्तकला उत्पाद लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए। इसके बाद उन्होंने 1.5 लाख रुपए कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड से तथा 4 लाख रुपए के क्रेडिट कैश लोन द्वारा गाँव में ही दुकान शुरू की और स्वयं-सहायता समूह की अन्य महिलाओं को जोड़कर उत्पादन बढ़ाना शुरू किया। आज उनके उत्पाद राज्य के बाहर भी पहुँचे हैं। वे एमेजोन जैसी विख्यात ऑनलाइन साइट्स पर भी बिक्री कर अपना व्यवसाय बढ़ा रही हैं। हाल में वे वार्षिक 10 लाख रुपए से अधिक आय अर्जित कर रही हैं और उनके कहे अनुसार उनकी इस सफलता में राज्य सरकार की ओर से लाइवलीहुड मिशन का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है।

कैसे काम करती है लखपति दीदी योजना ?

यह योजना स्वयं-सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने में सहायक बनती है, जिससे उनकी वार्षिक आय एक लाख रुपए से अधिक हो सके। महिलाएँ कृषि, पशुपालन, हस्तकला तथा अन्य स्थानीय क्षेत्रों में व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। इसके लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं द्वारा प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता तथा बाजार से कनेक्टिविटी की सुविधा दी जाती है, जिससे उनकी आय बढ़ सके। केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार लखपति दीदी के लिए निम्न विवरण अनुसार आय की गणना की जाती है :

- कृषि एवं सम्बद्ध व्यवसाय की कुल वार्षिक आय।
- नॉन-फार्म एक्टिविटी जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज आदि की आय।
- परिवार में कोई व्यक्ति नौकरी करता हो, तो उसकी आय।
- फार्म तथा नॉन-फार्म व्यवसाय में मजदूरी कार्य से प्राप्त आय।
- सरकार के योजनागत लाभ द्वारा प्राप्त राशि।
- कमिशन, मानद् वेतन से प्राप्त आय।

नमो ड्रोन दीदी योजना से भावनाबेन को मिली नई पहचान

बनासकाँठा में काँकरेज तहसील के वरसाडा की निवासी भावनाबेन भरतकुमार चौधरी ने ड्रोन दीदी बनकर आसपास के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने बीए तक पढ़ाई की है और वे पशुपालन-खेती के व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना अंतर्गत ड्रोन द्वारा कीटनाशक का छिड़काव करने के प्रशिक्षण के लिए उनका चयन होने के बाद वे काँकरेज तहसील में ड्रोन दीदी के रूप में जानी जाती हैं। वे गाँव में रहकर अपने सपने साकार कर रही हैं और आसपास की महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरणा दे रही हैं। उल्लेखनीय है कि कक्षा 10 उत्तीर्ण न्यूनतम योग्यता के साथ 18 से 60 वर्ष आयु समूह की महिलाएँ नमो ड्रोन दीदी योजना अंतर्गत ड्रोन पायलट बन सकती हैं।

248 मास्टर ट्रेनर्स द्वारा 10 हजार से अधिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को प्रशिक्षण

इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए गुजरात सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। तहसील स्तर पर 248 मास्टर ट्रेनर्स की नियुक्ति की गई है, जिन्होंने अब तक 10 हजार से अधिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स को प्रशिक्षण दिया है। ये कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स स्वयं-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को सहयोग देंगे। इस समग्र प्रक्रिया के लिए डिजिटल आजीविका रजिस्टर पर डेटा अपडेट किया जाता है, जो देखरेख के साथ महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण, वित्तीय सहयोग एवं मार्केट कनेक्टिविटी देने में सहायक होता है।

राज्य में 10 लाख से अधिक संभावित लखपति दीदी की पहचान

राज्य के प्रशिक्षित कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (सीआरपी) द्वारा हाल में 10.74 लाख महिलाओं की पहचान की गई है, जो लखपति दीदी बन सकती हैं। चिह्नित की गईं संभावित लखपति दीदी की मौजूदा गतिविधियों तथा उनके पास उपलब्ध स्रोतों, हुए खर्च और आय का विवरण प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल आजीविका रजिस्टर तैयार किया गया है। इस रजिस्टर से प्राप्त जानकारी के आधार पर चिह्नित की गईं लखपति दीदी को उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण, एसेट, आर्थिक सहायता तथा मार्केटिंग के लिए आवश्यक सपोर्ट किया जा रहा है।

यात्री सुविधा एवं अवसंरचना विकास हेतु ट्रैफिक ब्लॉक के कारण भावनगर मंडल की कुछ ट्रेनों के संचालन में अस्थायी परिवर्तन

यात्रियों को सूचित किया जाता है कि पश्चिम रेलवे के मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में छठी लाइन के कमीशनिंग कार्य के लिए ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक लिया जा रहा है। यह कार्य रेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा भविष्य में अधिक सुचारु रेल परिचालन सुनिश्चित करने की दिशा में किया जा रहा है। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि उक्त कार्य के दौरान भावनगर रेलवे मंडल से संबंधित कुछ मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन में अस्थायी परिवर्तन किए गए हैं। प्रभावित ट्रेनों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है:-

1.ट्रेन नंबर 19218 वेरावल-बान्द्रा एक्सप्रेस 27.12.2025 को 01 घंटा रिशेड्यूल होगी अर्थात वेरावल से 01 घंटा विलंब से चलेगी।

2.ट्रेन नंबर 19218 वेरावल-बान्द्रा

एक्सप्रेस 10.01.2026 को 45 मिनट रिशेड्यूल होगी अर्थात् वेरावल से 45 मिनट विलंब से चलेगी।

3.ट्रेन नंबर 19218 वेरावल-बान्द्रा एक्सप्रेस 15.01.2026 को 45 मिनट रिशेड्यूल होगी अर्थात् वेरावल से 45 मिनट विलंब से चलेगी।

4.ट्रेन नंबर 19218 वेरावल-बान्द्रा एक्सप्रेस 16.01.2026 को 30 मिनट रिशेड्यूल होगी अर्थात् वेरावल से 30 मिनट विलंब से चलेगी।

5.ट्रेन नंबर 12972 भावनगर-बान्द्रा सुपरफास्ट 27.12.2025 को मार्ग में 45 मिनट रिशेड्यूल होगी अर्थात् मार्ग में 45 मिनट विलंब होगी।

6.ट्रेन नंबर 19218 वेरावल-बान्द्रा एक्सप्रेस 06.01.2026 को मार्ग में 15 से 20 मिनट रिशेड्यूल होगी अर्थात् मार्ग में 15 से 20 मिनट विलंब होगी।

7.ट्रेन नंबर 19218 वेरावल-बान्द्रा एक्सप्रेस 07.01.2026 को मार्ग में 15 से 20 मिनट रिशेड्यूल होगी अर्थात् मार्ग में 15 से 20 मिनट विलंब होगी।

8.ट्रेन नंबर 19218 वेरावल-बान्द्रा एक्सप्रेस 13.01.2026 को मार्ग में 15 से 20 मिनट रिशेड्यूल होगी अर्थात् मार्ग में 15 से 20 मिनट विलंब होगी।

9.ट्रेन नंबर 19218 वेरावल-बान्द्रा एक्सप्रेस 14.01.2026 को मार्ग में 15 से 20 मिनट रिशेड्यूल होगी अर्थात् मार्ग में 15 से 20 मिनट विलंब होगी।

10.ट्रेन नंबर 09208 वेरावल-बान्द्रा टीओडी स्पेशल 15.01.2026 को मार्ग में 20 मिनट रिशेड्यूल होगी अर्थात् मार्ग में 20 मिनट विलंब होगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा से पूर्व NTES ऐप, रेलवे पूछताछ (139) अथवा अधिकृत रेलवे वेबसाइट के माध्यम से अपनी ट्रेन की स्थिति की पुष्टि कर लें। आरक्षित यात्रियों को SMS अलर्ट के माध्यम से भी जानकारी प्रदान की जा रही है।

पश्चिम रेलवे यात्रियों से इस असुविधा के लिए खेद प्रकट करता है तथा सहयोग की अपेक्षा करता है। यह कार्य पूर्ण होने के पश्चात यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित एवं समयबद्ध रेल सेवाओं का लाभ मिलेगा।

पश्चिम रेलवे का 45वाँ अधिकारियों का वार्षिक खेलकूद समारोह-क्रिकेट टूर्नामेंट में अहमदाबाद मंडल की शानदार जीत

पश्चिम रेलवे द्वारा आयोजित 45वें अधिकारियों के वार्षिक खेलकूद समारोह के अंतर्गत क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में पश्चिम रेलवे के विभिन्न मंडलों एवं मुख्यालय की टीमें भाग ले रही हैं। पश्चिम रेलवे 45वीं अधिकारियों की खेलकूद प्रतियोगिता क्रिकेट टूर्नामेंट 2025–26 टूर्नामेंट का दूसरा मैच आज दिनांक 20 दिसंबर 2025 को अहमदाबाद मंडल स्पोर्ट्स ग्राउंड (ADSA), साबरमती में खेला गया।

इस क्रिकेट मैच के दौरान अहमदाबाद मण्डल के मण्डल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश और मण्डल रेल प्रबंधक-भावनगर श्री दिनेश वर्मा भी मौजूद रहे। इस मैच में अहमदाबाद मंडल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट पर 182 रन बनाए। जवाब में भावनगर मंडल की टीम 20 ओवरों में 7 विकेट पर 118 रन ही बना सकी। इस प्रकार अहमदाबाद मंडल ने यह मैच 64 रनों से जीत लिया। श्री प्रशांत सिंह Dy CE III अहमदाबाद के इस मैच के प्रमुख खिलाड़ी रहे, इन्होने शतक लगा कर

अपनी टीम को विजय दिलाई तथा मैच ऑफ द मैच एवं बेस्टमेन रहे। बेस्ट बॉलर श्री विकास कुमार,Sr DSTE अहमदाबाद रहे। यह मैच खेल भावना, टीमवर्क एवं आपसी सहयोग का अच्छा उदाहरण रहा।

लीग चरण का कार्यक्रम

ग्रुप 'A'

- राजकोट बनाम अहमदाबाद – 13 दिसंबर 2025, प्रातः 09:30 बजे (राजकोट)
- अहमदाबाद बनाम भावनगर – 20 दिसंबर 2025, प्रातः 09:30 बजे (अहमदाबाद)
- वडोदरा बनाम राजकोट – 20 दिसंबर 2025, प्रातः 09:30 बजे (वडोदरा)
- भावनगर बनाम वडोदरा – 27 दिसंबर 2025, प्रातः 09:30 बजे (राजकोट)
- अहमदाबाद बनाम वडोदरा – 03 जनवरी 2026, प्रातः 09:30 बजे (अहमदाबाद)
- राजकोट बनाम भावनगर – 04 जनवरी 2026, प्रातः 09:30 बजे (भावनगर)

ग्रुप 'B'

- रतलाम बनाम मुंबई सेंट्रल (BCT) – 21 दिसंबर 2025, प्रातः 09:30 बजे (रतलाम)
- मुख्यालय 'A' बनाम मुख्यालय 'B' – 21 दिसंबर 2025, प्रातः 09:30 बजे (महालक्ष्मी)
- रतलाम बनाम मुख्यालय 'A' – 28 दिसंबर 2025, प्रातः 09:30 बजे (महालक्ष्मी)
- मुख्यालय 'B' बनाम मुंबई सेंट्रल (BCT) – 02 जनवरी 2026, प्रातः 09:30 बजे (महालक्ष्मी)
- मुख्यालय 'A' बनाम मुंबई सेंट्रल (BCT) – 03 जनवरी 2026, प्रातः 09:30 बजे (महालक्ष्मी)
- मुख्यालय 'B' बनाम रतलाम – 04 जनवरी 2026, प्रातः 09:30 बजे (महालक्ष्मी)

नॉकआउट चरण

प्रथम सेमीफाइनल – 10 जनवरी 2026, प्रातः 09:30 बजे (ग्रुप 'A' विजेता बनाम ग्रुप 'B' उपविजेता)

द्वितीय सेमीफाइनल – 11 जनवरी 2026, प्रातः 09:30 बजे (ग्रुप 'B' विजेता बनाम ग्रुप 'A' उपविजेता)

फाइनल मुकाबला – 23 जनवरी 2026, प्रातः 10:00 बजे (महालक्ष्मी मैदान)

इस तरह की खेल प्रतियोगिताएँ अधिकारियों में स्वास्थ्य, उत्साह और आपसी सौहार्द को बढ़ावा देती हैं। यह क्रिकेट टूर्नामेंट अधिकारियों में खेल भावना, टीमवर्क एवं आपसी समन्वय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।

तराई के जंगलों में कानून के रखवाले ही कटघरे में, लकड़ी तस्करी के विरोध पर वनकर्मी से मारपीट और पिस्टल तानने का आरोप

हल्द्वानी। तराई केंद्रीय वन प्रभाग में लकड़ी तस्करी को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जंगलों की रक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले विभाग के भीतर ही कथित मिलीभगत और दबाव की तस्वीर सामने आई है। लकड़ी की अवैध तस्करी रोकने की कोशिश करने वाले एक प्लांटेशन वाचर ने अपने ही विभाग के एसओजी प्रभारी पर तस्करों को संरक्षण देने, मारपीट करने और सिर पर पिस्टल तानकर धमकाने जैसे बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। मामला सामने आते ही वन विभाग में हड़कंप मच गया है और उच्च स्तर पर जांच के निर्देश दिए गए हैं।

यह पूरा मामला बाजपुर क्षेत्र के ग्राम महोली जंगल से जुड़ा बताया जा रहा है। पकड़िया चौकी में तैनात प्लांटेशन वाचर ज्ञान सिंह के अनुसार, वह ड्यूटी पूरी कर घर लौट रहे थे, तभी चौकी से कुछ दूरी पर जंगल क्षेत्र में लकड़ी की अवैध तस्करी होती दिखाई दी। आरोप है कि मौके पर खैर और सागौन जैसी कीमती लकड़ी डंपर में लादी जा रही थी। जब उन्होंने इसका विरोध किया और तस्करी रोकने की कोशिश की, तो वहां मौजूद तस्करों ने उनके साथ मारपीट की।

ज्ञान सिंह का आरोप है कि इस दौरान तराई केंद्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर के एसओजी प्रभारी कैलाश चंद्र तिवारी मौके पर पहुंचे, लेकिन तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्होंने डंपर को वहां से निकलवा दिया। वाचर का कहना है कि जब उन्होंने दोबारा अवैध तस्करी का विरोध किया और सवाल उठाए, तो एसओजी प्रभारी ने उनके साथ भी मारपीट की और रिवॉल्वर उनके सिर पर रखकर चुप रहने की धमकी दी। आरोप है कि उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की बात भी कही गई, ताकि वे इस पूरे मामले को उजागर न कर सकें।

घटना के बाद ज्ञान सिंह ने उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत देकर पूरे मामले की जानकारी दी है। शिकायत में उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग की है। वाचर के आरोपों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली और जंगलों में सक्रिय लकड़ी तस्करी नेटवर्क को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या तस्करों को विभाग के भीतर से संरक्षण मिल रहा है।

वहीं दूसरी ओर, एसओजी प्रभारी कैलाश चंद्र तिवारी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। उनका कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि प्लांटेशन वाचर ज्ञान सिंह नशे की हालत में हंगामा कर रहा था और महिला वनकर्मियों से अभद्र व्यवहार कर रहा था। इसी सूचना पर वे मौके पर पहुंचे थे और स्थिति को नियंत्रित किया गया। उन्होंने किसी भी प्रकार की मारपीट, धमकी या हथियार तानने के आरोपों को झूठा और निराधार बताया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य वन संरक्षक (पश्चिमी वृत्त) साकेत बड़ोला ने कहा कि लगाए गए आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं और इन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने बताया कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और गहन जांच कराई जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो।

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जंगलों की सुरक्षा और अवैध लकड़ी तस्करी पर रोक लगाने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर है, अगर वही संदेह के घेरे में आ जाएं तो सिस्टम पर लोगों का भरोसा कैसे कायम रहेगा। अब सभी की नजरें जांच के नतीजों पर टिकी हैं, जो यह तय करेंगे कि यह मामला तस्करी रोकने वाले एक ईमानदार कर्मचारी के उत्पीड़न का है या फिर विभागीय अनुशासन से जुड़ा कोई और सच सामने आएगा।

महिला सम्मान के सवाल पर मायावती का नीतीश सरकार पर प्रहार, हिजाब विवाद को बताया शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण

लखनऊ। बिहार में एक मुस्लिम महिला डॉक्टर से जुड़े हिजाब विवाद को लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को न सिर्फ दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया, बल्कि इसे सीधे तौर पर महिला सम्मान और सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला करार दिया। मायावती ने कहा कि ऐसे संवेदनशील प्रकरणों में संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। अगर समय रहते मुख्यमंत्री स्तर पर हस्तक्षेप किया जाता, तो यह विवाद इतना नहीं बढ़ता। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बेहतर होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले पर पश्चाताप करें और इसे यहीं समाप्त करें, ताकि समाज में गलत संदेश न जाए।

मायावती ने कहा कि भारत विविधताओं वाला देश है, जहां हर नागरिक को अपने धर्म, पहनावे और व्यक्तिगत आस्था के अनुसार जीवन जीने का संवैधानिक अधिकार है। किसी महिला के पहनावे को लेकर सार्वजनिक मंच पर सवाल उठाना या दबाव बनाना न केवल उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के भी खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि ऐसे मामलों को हल्के में लेने से सामाजिक सौहार्द और आपसी विश्वास कमजोर होता है, जिसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। बसपा प्रमुख ने इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस परेड के दौरान कथावाचक को सलामी दिए जाने के मामले पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पुलिस परेड की अपनी एक तय मर्यादा, अनुशासन और परंपरा होती है, जिनका सख्ती से पालन होना चाहिए। किसी भी तरह की ढिलाई या प्रतीकात्मक दिखावे से पुलिस बल की गरिमा और अनुशासन पर असर पड़ता है। मायावती ने इस मामले में पुलिस महानिदेशक द्वारा संज्ञान लेने को सही कदम बताया और उम्मीद जताई कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

इसके अलावा मायावती ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह सत्र जनहित के गंभीर मुद्दों पर ठोस चर्चा करने का अवसर था, लेकिन सरकार और सत्ता पक्ष ने इसे भटकाने का काम किया। खासकर किसानों की खाद की समस्या, महंगाई, बेरोजगारी और आम जनता से जुड़े अन्य सवालों पर गंभीर विमर्श होना चाहिए था, जो नहीं हो सका।

अहमदाबाद को मिली उसकी पहली 'मेक इन इंडिया' मेट्रो ट्रेन

- मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कोलकाता स्थित टीटागढ़ रेल सिस्टम्स प्लांट में गुजरात की सांस्कृतिक भावना को प्रतिबिंबित करने वाली अत्याधुनिक एवं आत्मनिर्भर भारत की प्रतीक समान ट्रेन का स्वागत किया
- यह मेट्रो ट्रेन श्रेष्ठ कोटि की फायर सेफ्टी सहित अन्य सुरक्षा सुविधाओं तथा ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन 4 (जीओए4) के अंतर्गत पूर्णतः ऑटोमेटेड-ड्राइवरलेस ट्रेन के रूप में कार्य करने में सक्षम है

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को अहमदाबाद शहर को उसकी प्रथम स्वदेशी रूप से निर्मित 'मेक इन इंडिया' मेट्रो ट्रेन की भेंट दी।

श्री पटेल ने कोलकाता के निकट टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के आधुनिक प्लांट का दौरा कर अहमदाबाद मेट्रो रेल के कोचेस लॉन्च किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'मेक इन इंडिया' तथा आत्मनिर्भर भारत को गति देने वाला यह महत्वपूर्ण कदम गुजरात के लिए गौरव समान है।

टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा उसके फैसिलिटी प्लांट में यह ट्रेन मेक इन इंडिया अंतर्गत स्वदेशी रूप से बनाई जा रही है। आधुनिक मेट्रो तथा यात्री कोच के उत्पादन के लिए सक्षम यह प्लांट अत्याधुनिक एवं आधुनिक तकनीक तथा साधन-सामग्री के साथ स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टीटागढ़ प्लांट में देश के अनेक राज्यों के लोग कार्यरत हैं। यह भी एक भारत-श्रेष्ठ भारत का प्रधानमंत्री का मंत्र चरितार्थ करता है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए अभिनंदन दिया।

उन्होंने कहा कि अहमदाबाद को मिल रही यह मेट्रो ट्रेन शहर में मेट्रो रेल व्यवस्था की बढ़ती मांग तथा लोकप्रियता को पूरा करने के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को सुगम बनाएगी। गुजरात मेट्रो रेल

कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीएमआरसीएल) ने कोलकाता स्थित टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड को 10 ट्रेनों का ऑर्डर दिया है। ये ट्रेनें फेज-2 के 21 किलोमीटर का कार्य पूर्ण होने पर तथा शेष भाग शीघ्र कार्यरत होने पर उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त ट्रेनों की जरूरत को पूरा करेंगी।

श्री भूपेंद्र पटेल ने जोड़ा कि अहमदाबाद मेट्रो हाल में प्रतिदिन 1.6 लाख से अधिक यात्रियों को सेवा देती है और इसमें वार्षिक 30-40 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। आने वाले दिनों में मेट्रो रेल सेवा का यह दायरा बढ़ाया जाएगा और सूरत में भी मेट्रो कार्यरत होने वाली है।

उन्होंने कहा कि उच्च गुणवत्ता वाले स्टेनलेस स्टील से बनी इन मेक इन इंडिया ट्रेनों में रंगों तथा डिजाइन का जो विशेष स्पर्श दिया गया है, वह अहमदाबाद की संस्कृति एवं परंपरा को प्रतिबिंबित करता है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि अहमदाबाद मेट्रो रेल के लिए स्वीकार की गई प्रथम मेक इन इंडिया मेट्रो ट्रेन अंतिम परीक्षणों तथा सम्बद्ध प्राधिकारियों से प्रमाणपत्र मिलने के बाद शीघ्र ही अहमदाबाद पहुँचाई जाएगी। इसके बाद उसे यात्रियों की सेवा में जोड़ा जाएगा। इतना ही नहीं; अहमदाबाद के लिए बाकी रही 9 ट्रेनें भी टीटागढ़ प्लांट द्वारा आगामी 5-6 महीनों में चरणबद्ध ढंग से प्रदान की जाएंगी। वैश्विक स्तर पर लागू होने वाले वर्तमान अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुकूल यह मेक इन इंडिया ट्रेन गुजरात के लिए गौरव समान बनेगी।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ऐसे विजनरी लीडर हैं कि वे हर कार्य में भावी आयोजन तथा छोटे से छोटे व्यक्ति के भले का विचार करके ही आगे बढ़ते हैं। उनके दिशादर्शन में देश के विकास में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, उसका विवरण देते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि पिछले वर्षों में देश में रिकॉर्ड ब्रेक गति से सड़क निर्माण हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है और मेक इन इंडिया सेमी हाईस्पीड वंदे भारत ट्रेन से रैपिड ट्रांजिस्ट को नई दिशा मिली है। 2014 में मेट्रो नेटवर्क 248 किलोमीटर था, जो 2025 में बढ़कर 1013 किलोमीटर हुआ है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कोच निरीक्षण के जरिये तथा प्लांट के वरिष्ठ इंजीनियरों के साथ चर्चा करते हुए अहमदाबाद मेट्रो ट्रेन के कोचेस की विशेषताओं की गहन जानकारी प्राप्त की। टीटागढ़ प्लांट के इंजीनियरों ने मुख्यमंत्री को बताया कि यह मेट्रो ट्रेन श्रेष्ठ कोटि की फायर सेफ्टी सहित अन्य सुरक्षा सुविधाओं तथा ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन 4 (जीओए4) अंतर्गत पूर्णतः ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन के रूप में कार्य करने में सक्षम है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया, मुख्यमंत्री के सलाहकार तथा गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री एस. एस. राठौड़, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के प्रबंध निदेशक श्री उमेश चौधरी, गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन तथा टीटागढ़ रेलवे सिस्टम्स के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

टीटागढ़ रेलवे सिस्टम्स प्लांट नेक्स्ट जनरेशन वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों तथा पुणे, बेंगलुरू, मुंबई, सूरत एवं अहमदाबाद जैसे अनेक शहरों के लिए मेट्रो ट्रेनों के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। इस प्लांट में भारत के महत्वाकांक्षी हाईस्पीड कार्यक्रम के लिए भविष्य में उच्च गति की ट्रेनें बनाने की क्षमता विकसित करने के लिए भी सुविधाओं का विकास कार्य शुरू किया गया है। इतना ही नहीं; कंपनी भारत की सबसे बड़ी वेगन उत्पादक कंपनी है और नौसेना तथा अन्य विशेष उपयोगों के लिए जहाजों का उत्पादन भी करती है।

आदरज मोटी–विजापुर रेलखंड पर इंजन स्पीड ट्रायल सफलता पूर्वक सम्पन्न

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल पर आदरज मोटी–विजापुर गेज परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत आदरज मोटी–विजापुर सेक्शन में नई परिवर्तित ब्रॉडगेज रेलवे लाइन पर 20 दिसंबर 2025 को लाइट इंजन का स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक किया गया। यह स्पीड ट्रायल किमी 6/4 से किमी 45/1 के बीच अधिकतम 136 किमी प्रति घंटे की गति से संपन्न हुआ। इस रेलवे लाइन के पूर्ण होने पर हाल ही में गेज परिवर्तित आंबलियासन-विजापुर लाइन से सीधी जुड़ जाएगी।

इस स्पीड ट्रायल के सफल आयोजन से आगामी समय में इस खंड पर तेज, सुरक्षित एवं सुगम रेल परिचालन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आंबलियासन को इस नई ब्रॉडगेज रेल लाइन से विशेष रूप से उत्तर गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी प्राप्त होगी, जिससे यात्रियों को समय की बचत के साथ अधिक सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी।

स्पीड ट्रायल रेलवे की एक अनिवार्य तकनीकी प्रक्रिया है, जो रेल परिचालन प्रारंभ करने से पूर्व ट्रैक की गुणवत्ता, स्थिरता एवं सुरक्षा मानकों की जांच हेतु की जाती है। इस दौरान विभागीय ट्रेनें, मापन यंत्र एवं तकनीकी विशेषज्ञों की टीम द्वारा ट्रैक का गहन परीक्षण किया गया।

एंबुलेंस के इंतजार में बुझ गई उम्मीद, थैले में बेटे का शव लेकर घर लौटा पिता

चाईबासा से सामने आई अमानवीय तस्वीर, झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा से सामने आई एक घटना ने पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह घटना न केवल प्रशासनिक लापरवाही का उदाहरण है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं पर भी गहरा आघात करती है। इलाज की उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंचे एक गरीब आदिवासी पिता को उस समय गहरा सदमा झेलना पड़ा, जब उसके चार महीने के मासूम बेटे की मौत के बाद शव ले जाने के लिए एंबुलेंस तक उपलब्ध नहीं कराई गई। मजबूरी और बेबसी की पराकाष्ठा यह रही कि पिता को अपने ही बेटे का शव एक थैले में रखकर पैदल और साधनों के सहारे गांव तक ले जाना पड़ा।

जानकारी के अनुसार, नवामुंडी प्रखंड के बाद बालजोड़ी गांव निवासी डिंबा चितोंबा अपने चार माह के बेटे को गंभीर हालत में सदर अस्पताल चाईबासा लेकर पहुंचे थे। परिजनों को उम्मीद थी कि अस्पताल में बच्चे को समय पर इलाज मिल जाएगा और उसकी जान बच जाएगी। लेकिन इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया। बेटे की मौत से टूट चुके पिता के सामने इसके बाद एक और कठिन परीक्षा खड़ी हो गई। अस्पताल प्रशासन से शव वाहन या एंबुलेंस की मांग की गई, लेकिन घंटों इंतजार के बावजूद कोई व्यवस्था नहीं हो सकी। न तो सरकारी एंबुलेंस उपलब्ध कराई गई और न ही किसी स्तर पर वैकल्पिक इंतजाम किया गया।

अंततः बेसहारा पिता ने मजबूरी में अपने चार महीने के बेटे के निर्जीव शरीर को एक थैले में रखा और उसी हालत में गांव के लिए रवाना हो गया। यह दृश्य जिसने भी देखा, उसकी आंखें नम हो गईं। जिस पिता ने बेटे को गोद में खिलाने और उसे बड़ा होते देखने के सपने संजोए थे, वही पिता अब उस मासूम को अंतिम यात्रा पर इस अमानवीय तरीके से ले जाने को मजबूर हुआ। यह तस्वीर सामने आते ही पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया और लोगों ने इसे झारखंड के स्वास्थ्य तंत्र की सबसे शर्मनाक मिसाल बताया।

घटना के उजागर होते ही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगीं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य गठन के 25 वर्षों बाद भी यदि एक गरीब पिता को अपने बच्चे का शव इस तरह ले जाना पड़े, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। उन्होंने इसे अमानवीय और प्रशासनिक असफलता करार देते हुए सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की।

मामले के तूल पकड़ने के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने भी संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि चाईबासा की यह घटना अत्यंत गंभीर है और जैसे ही मामला उनके संज्ञान में आया, उन्होंने तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने और सिविल सर्जन से पूरे मामले पर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब करने की बात कही। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सेवाओं में इस तरह की लापरवाही को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इसके बावजूद यह घटना कई सवाल छोड़ जाती है। क्या केवल जांच और आश्वासन से उस पिता के जख्म भर पाएंगे, जिसने अपने बेटे को थैले में उठाकर घर तक पहुंचाया? यह घटना उन सरकारी दावों की भी पोल खोलती है, जिनमें बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, मुफ्त इलाज और 24 घंटे एंबुलेंस सुविधा की बात की जाती है। चाईबासा की यह तस्वीर झारखंड ही नहीं, बल्कि पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर करती है कि जब तक योजनाएं जमीनी स्तर पर संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ लागू नहीं होंगी, तब तक ऐसे दर्दनाक दृश्य बार-बार सामने आते रहेंगे।

टाटीसिलवे स्टेशन पर इंसानियत शर्मसार, सेना के जवान ने ट्रेन की खाली बोगी में युवती से किया दुष्कर्म, रांची में मचा हड़कंप

झारखंड की राजधानी रांची एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। टाटीसिलवे रेलवे स्टेशन पर हुई दुष्कर्म की इस सनसनीखेज घटना ने न केवल रेल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है, बल्कि समाज को भी झकझोर कर रख दिया है। आरोप देश की सेवा में तैनात एक सेना के जवान पर लगा है, जिसने भरोसे और बातचीत का सहारा लेकर एक युवती के साथ दरिंदगी की हदें पार कर दीं। पीड़िता की शिकायत के बाद रेलवे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन यह घटना कई ऐसे सवाल छोड़ गई है जिनका जवाब सिस्टम को देना होगा।

जानकारी के अनुसार यह घटना 18 दिसंबर की रात की है। पीड़िता टाटीसिलवे रेलवे स्टेशन पर रांची जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान आरोपी जवान, जिसकी पहचान अजीत सिंह के रूप में हुई है, युवती से बातचीत करने लगा। बातचीत के दौरान उसने खुद को भरोसेमंद साबित करने की कोशिश की और बहला-फुसलाकर स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन की खाली बोगी की ओर ले गया। आरोप है कि वहां उसने युवती को धमकाया और जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती जब तक कुछ समझ पाती, उससे पहले ही आरोपी ने उसकी मजबूरी और डर का फायदा उठाकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दे दिया।

घटना के दौरान जब पीड़िता ने खुद को बचाने के लिए शोर मचाया, तो प्लेटफॉर्म पर तैनात जीआरपी के जवानों का ध्यान इस ओर गया। पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी जवान ने पुलिसकर्मियों को धक्का देकर भागने का प्रयास किया। हालांकि, रेलवे पुलिस की सतर्कता और तेजी के कारण वह ज्यादा दूर नहीं जा सका और कुछ ही देर में उसे काबू कर लिया गया। इसके बाद आरोपी को हिरासत में लेकर रेल थाना रांची लाया गया, जहां पीड़िता की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया।

गिरफ्तार आरोपी अजीत सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का निवासी बताया जा रहा है और वर्तमान में पंजाब के पटियाला स्थित 42 मीडियम रेजिमेंट में तैनात है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया और आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। फिलहाल मामले की गहन जांच की जा रही है और पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है।

यह घटना इसलिए भी ज्यादा चिंता पैदा करती है क्योंकि इससे पहले भी झारखंड में सुरक्षा बलों से जुड़े लोगों पर इस तरह के गंभीर आरोप सामने आ चुके हैं। जनवरी 2025 में रांची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में इलाज के लिए पहुंची एक युवती के साथ सैप के जवान द्वारा दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसमें आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया गया था। एक के बाद एक सामने आ रही ऐसी घटनाएं यह सवाल उठाती हैं कि जिन पर नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, यदि वही कानून को हाथ में लेने लगें तो आम जनता खुद को कितना सुरक्षित महसूस करेगी।

टाटीसिलवे स्टेशन की यह घटना न सिर्फ एक अपराध की कहानी है, बल्कि यह रेलवे परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की जवाबदेही पर भी बड़ा प्रश्नचिह्न है। अब सभी की निगाहें जांच और न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी हैं, ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

सरकारी वादों की फाइलों में उलझी शिक्षा व्यवस्था, उत्तराखंड में 9 महीने बाद भी 10 लाख छात्रों को नहीं मिलीं मुफ्त कॉपियां

देहरादून। उत्तराखंड सरकार द्वारा कक्षा एक से बारहवीं तक के छात्र-छात्राओं को मुफ्त कॉपियां देने का जो वादा किया गया था, वह पूरे शैक्षिक सत्र में सिर्फ घोषणा बनकर रह गया। शैक्षणिक वर्ष समाप्ति की ओर है, लेकिन प्रदेश के करीब 10 लाख छात्र अब भी मुफ्त कॉपियों के इंतजार में हैं। हालात यह हैं कि बच्चों ने पूरा साल बिना सरकारी कॉपियों के पढ़ाई पूरी की और अब विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की औपचारिकता निभाई है, जिससे शिक्षा व्यवस्था की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

सरकार ने इस योजना की घोषणा बड़े स्तर पर की थी। कहा गया था कि जैसे छात्रों को मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म दी जाती हैं, उसी तरह कॉपियां भी बिना किसी खर्च के उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि अभिभावकों पर आर्थिक बोझ कम हो और गरीब व मध्यम वर्ग के बच्चों को पढ़ाई में कोई बाधा न आए। इस योजना के तहत सरकारी और अशासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा एक से बारहवीं तक के लाखों छात्रों को लाभ मिलना था। अप्रैल 2025 में इस प्रस्ताव को कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई थी, जिससे यह उम्मीद बनी कि जल्द ही कॉपियां छात्रों तक पहुंचेंगी।

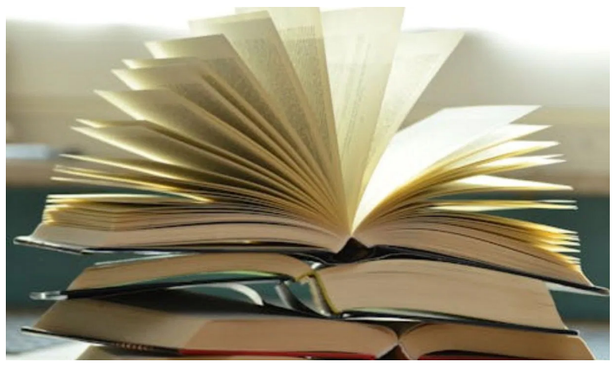

लेकिन हकीकत यह रही कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद भी महीनों तक फाइलें इधर-उधर घूमती रहीं और जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अप्रैल से दिसंबर तक पूरे नौ महीने बीत गए, शैक्षणिक सत्र लगभग खत्म हो गया, लेकिन छात्रों के हाथों में मुफ्त कॉपियां नहीं पहुंच सकीं। इस दौरान बच्चों और अभिभावकों को मजबूरी में बाजार से कॉपियां खरीदनी पड़ीं, जिससे योजना का मूल उद्देश्य ही खत्म हो गया।

अब जाकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती ने इस संबंध में विभाग के सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए छात्रों को मुफ्त कॉपियां उपलब्ध कराई जानी हैं और इसके लिए चार दिसंबर 2025 को ऑनलाइन ई-निविदा आमंत्रित की गई है। यानी जिस योजना का लाभ चालू सत्र में मिलना था, उसकी प्रक्रिया अगले सत्र के नाम पर अब शुरू की जा रही है। इससे यह सवाल और गहरा गया है कि जब टेंडर प्रक्रिया अब शुरू हुई है तो छात्रों तक कॉपियां कब पहुंचेंगी और क्या अगले सत्र की शुरुआत में भी बच्चों को इसी तरह इंतजार करना पड़ेगा।

शिक्षा विभाग की इस देरी को लेकर अभिभावकों और शिक्षाविदों में नाराजगी साफ देखी जा रही है। उनका कहना है कि अगर सरकार ने समय रहते योजना को लागू किया होता तो लाखों छात्रों को राहत मिलती। खासकर ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले गरीब परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त कॉपियां एक बड़ी मदद साबित हो सकती थीं। लेकिन लापरवाही और सुस्त प्रशासनिक प्रक्रिया के चलते पूरा साल निकल गया और बच्चे इस सुविधा से वंचित रह गए।

इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि योजनाओं की घोषणा और उनके क्रियान्वयन के बीच का अंतर उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था की बड़ी कमजोरी बनता जा रहा है। सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार अधिकारियों से इस देरी की जवाबदेही तय होगी, या फिर हर साल की तरह यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा और छात्र केवल वादों के सहारे ही पढ़ाई करने को मजबूर रहेंगे।

कोडीन कफ सिरप तस्करी पर योगी सरकार का कड़ा प्रहार, दोषी चाहे जितना प्रभावशाली हो बख्शा नहीं जाएगा: सुरेश खन्ना

शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी को लेकर योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि इस मामले में किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने शनिवार को शाहजहांपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई पूरी पारदर्शिता और कठोरता के साथ की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस अवैध कारोबार में चाहे कोई कितना ही बड़ा या प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो, यदि दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे।

मंत्री सुरेश खन्ना ने इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि कोडीन माफिया से जुड़े एक व्यक्ति के साथ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर सामने आई है, जिसे लेकर अब सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि ऐसे में गोलमोल बयान देने या बात को टालने के बजाय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को चाहिए कि वह इस तस्वीर की सच्चाई देश और प्रदेश की जनता के सामने स्पष्ट करें। खन्ना ने कहा कि पूरा देश जानना चाहता है कि यह तस्वीर किस संदर्भ में ली गई और इसके पीछे की वास्तविकता क्या है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कोडीन युक्त कफ सिरप के दुरुपयोग से देश के कई हिस्सों में बच्चों की मौत जैसी गंभीर घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस संवेदनशील मुद्दे पर न तो कोई ठोस प्रतिक्रिया दी और न ही चिंता जताई। सुरेश खन्ना ने कहा कि नशीले पदार्थों की बड़े पैमाने पर तस्करी एक गंभीर सामाजिक अपराध है, लेकिन विपक्ष ने इस पर चुप्पी साधे रखी। उन्होंने दावा किया कि इस पूरे नेटवर्क में पकड़े गए कई लोगों के किसी न किसी रूप में समाजवादी पार्टी से संबंध उजागर हुए हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में अब तक कोडीन युक्त कफ सिरप के सेवन से किसी भी तरह की मौत की पुष्टि नहीं हुई है, इसके बावजूद योगी सरकार ने मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त बनाना है और इसी उद्देश्य के तहत यह अभियान पूरी सख्ती के साथ चलाया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि कोडीन युक्त कफ सिरप एक नियंत्रित दवा है, जिसे केवल डॉक्टर की सलाह पर गंभीर खांसी के मरीजों को दिया जाता है। मेडिकल स्टोर संचालकों के लिए इस दवा की बिक्री और स्टॉक का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है, लेकिन जांच में सामने आया कि इसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग करते हुए अवैध रूप से तस्करी की जा रही थी।

जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि कोडीन युक्त कफ सिरप को नशे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में भेजा जा रहा था। इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए सरकार ने एफएसडीए और पुलिस के सहयोग से विशेष जांच दल का गठन किया है। मंत्री ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक (कानून-व्यवस्था) एलआर कुमार की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और हर कड़ी को खंगाला जा रहा है।

सुरेश खन्ना ने बताया कि अब तक प्रदेश के 33 जनपदों में 140 फर्मों के खिलाफ बीएनएस और एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। इस कार्रवाई के तहत 75 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 9.42 करोड़ रुपये मूल्य का कोडीन युक्त कफ सिरप जब्त किया गया है। कुल 12 लाख 65 हजार 455 बोतलें बरामद की गई हैं, जो इस अवैध कारोबार के व्यापक नेटवर्क की ओर इशारा करती हैं। मंत्री ने दो टूक कहा कि एसआईटी की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, इस तस्करी से जुड़े हर व्यक्ति को कानून के दायरे में लाया जाएगा और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में चुनावी सियासत में उठे धार्मिक मुद्दे: हुमायूं कबीर और जाकिर हुसैन के मंदिर-मस्जिद निर्माण के ऐलान से गरमा उठा राजनीतिक माहौल

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सूबे की सियासत पहले ही गर्म है। ऐसे में हाल ही में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर और पार्टी के अन्य विधायक जाकिर हुसैन के विवादित ऐलान ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करते हुए मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा क्षेत्र में आधारशिला रखी, वहीं जाकिर हुसैन ने श्री कृष्ण मंदिर निर्माण की घोषणा कर दी। इन घोषणाओं ने राज्य में राजनीतिक दलों और समुदायों के बीच चर्चा का नया दौर शुरू कर दिया है।

हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर सीट से विधायक हैं और हाल ही में बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए मैदान में उतरकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ फीता काटकर मस्जिद की नींव रखी और कहा कि उनका उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक सौहार्द बनाए रखना है। हालांकि, पार्टी ने उनके इस कदम पर आपत्ति जताते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद वह किंगमेकर के रूप में उभरेंगे और उनकी नई राजनीतिक पार्टी के समर्थन के बिना राज्य में कोई सरकार बहुमत से नहीं बन पाएगी। उन्होंने संकेत दिया कि उनकी नई पार्टी की औपचारिक घोषणा 22 दिसंबर को होगी और वे लगभग 135 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।

वहीं जाकिर हुसैन, जो मुर्शिदाबाद के जंगीपुर क्षेत्र से टीएमसी के विधायक और पूर्व श्रम विभाग के राज्य मंत्री रह चुके हैं, ने श्री कृष्ण मंदिर निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मंदिर की अनुमानित लागत 1 करोड़ रुपए होगी। इसके साथ ही उन्होंने मुर्शिदाबाद में मोहम्मदी मस्जिद निर्माण की भी बात कही। जाकिर हुसैन ने धार्मिक सामंजस्य की ओर इशारा करते हुए कहा कि गीता और कुरान में 85 प्रतिशत समानताएं हैं, जो दोनों समुदायों के बीच मेलजोल और सह-अस्तित्व को दर्शाती हैं।

राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि हुमायूं कबीर और जाकिर हुसैन की घोषणाएं चुनावी रणनीति का हिस्सा मानी जा सकती हैं। अगले साल विधानसभा चुनावों से पहले धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा और अधिक तीव्र हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि हुमायूं कबीर का किंगमेकर बनने का दावा और जाकिर हुसैन का मंदिर निर्माण का ऐलान भाजपा, TMC और अन्य दलों के चुनावी गणित को प्रभावित कर सकता है।

राज्य में पिछले चुनावों के अनुभव के आधार पर देखा जाए तो धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दे हमेशा चुनावी रण में अहम भूमिका निभाते आए हैं। हुमायूं कबीर ने अपने बयानों में यह भी कहा कि 294 सदस्यीय विधानसभा में कोई भी पार्टी 148 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आगामी चुनावों में गठबंधन और समर्थन की राजनीति प्रमुख रहेगी। जाकिर हुसैन की घोषणा ने इस गणित को और जटिल बना दिया है।

इस प्रकार पश्चिम बंगाल की सियासत में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले धार्मिक मुद्दों को लेकर चर्चाएं और विवाद बढ़ रहे हैं। हुमायूं कबीर और जाकिर हुसैन की घोषणाओं ने राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को और गर्म कर दिया है और यह स्पष्ट है कि चुनाव के दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दे चुनावी रणनीति का हिस्सा बनकर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।

सप्ताह के दौरान सोना वायदा में 2052 रुपये और चांदी वायदा में 4623 रुपये का ऊछाल: क्रूड ऑयल वायदा 85 रुपये फिसला

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर 12 से 18 दिसंबर के सप्ताह के दौरान कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस, इंडेक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में 3413665.58 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 459713.24 करोड़ रुपये का साप्ताहिक कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 2953864.13 करोड़ रुपये का साप्ताहिक नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का दिसंबर वायदा 33065 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में सप्ताह के दौरान कुल प्रीमियम टर्नओवर 42095.17 करोड़ रुपये का हुआ।

आलौच्य अवधि के सप्ताह के दौरान कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 377216.12 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में 132442 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 135590 रुपये के उच्च और 132275 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 132469 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 2052 रुपये या 1.55 फीसदी की तेजी के संग 134521 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-गिनी दिसंबर वायदा सप्ताह के अंत में 1899 रुपये या 1.8 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 107605 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल दिसंबर वायदा सप्ताह के अंत में 203 रुपये या 1.53 फीसदी की तेजी के संग 13442 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर पहुंचा। सोना-मिनी जनवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में 130905 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 133633 रुपये के उच्च और 130400 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 1779 रुपये या 1.36 फीसदी की मजबूती के साथ 132684 रुपये प्रति 10 ग्राम बंद हुआ। गोल्ड-टेन दिसंबर वायदा प्रति 10 ग्राम सप्ताह के आरंभ में 131334 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 133870 रुपये के उच्च और 130681 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 131137 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 1818 रुपये या 1.39 फीसदी की बढ़त के साथ 132955 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सप्ताह के आरंभ में 196958 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 207833 रुपये और नीचे में 190077 रुपये पर पहुंचकर, 198942 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 4623 रुपये या 2.32 फीसदी ऊछलकर 203565 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा सप्ताह के अंत में 5054 रुपये या 2.54 फीसदी की तेजी के संग 204264 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 5046 रुपये या 2.53 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट सप्ताह के अंत में 204269 रुपये प्रति किलो पर आ गया। मेटल वर्ग में 35491.31 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा दिसंबर वायदा 15 पैसे या 0.01 फीसदी की नरमी के साथ 1111.7 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि जस्ता दिसंबर वायदा 17.65 रुपये या 5.51 फीसदी लुढ़ककर 302.45 रुपये प्रति किलो बंद हुआ। इसके सामने एल्यूमीनियम दिसंबर वायदा 1.5 रुपये या 0.53 फीसदी बढ़कर 282.2 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। जबकि सीसा दिसंबर वायदा 50 पैसे या 0.27 फीसदी घटकर 181.4 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ।

कमोडिटी वायदाओं में 459713.24 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 2953864.13 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ साप्ताहिक टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 377216.12 करोड़ रुपये का हुआ साप्ताहिक कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 33065 पॉइंट के स्तर पर

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 46955.54 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल जनवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में 5277 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 5277 रुपये और नीचे में 5038 रुपये पर पहुंचकर, 85 रुपये या 1.63 फीसदी गिरकर 5114 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी जनवरी वायदा 87 रुपये या 1.67 फीसदी की गिरावट के साथ 5116 रुपये प्रति बैरल के भाव पर बंद हुआ। इनके अलावा नैचुरल गैस दिसंबर वायदा 380.9 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 386.2 रुपये और नीचे में 350.8 रुपये पर पहुंचकर, 381.1 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 24.9 रुपये या 6.53 फीसदी गिरकर 356.2 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा। जबकि नैचुरल गैस-मिनी दिसंबर वायदा 25 रुपये या 6.56 फीसदी लुढ़ककर 356.3 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बंद हुआ।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल दिसंबर वायदा 909.5 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 33.9 रुपये या 3.72 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 944.9 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सप्ताह के दौरान सोना के विभिन्न अनुबंधों में 187732.01 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 189484.11 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 28257.61 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 2181.02 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 230.74 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 4821.93 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 8760.12 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 38126.92 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

सप्ताह के अंत में ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 14316 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 43496 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 6203 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 90580 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 9444 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 12888 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 29432 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 57672 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 21437 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 16132 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स दिसंबर वायदा सप्ताह के आरंभ में 32632 पॉइंट पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 33370 के उच्च और 32086 के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 502 पॉइंट बढ़कर 33065 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ।